

>

Title: Regarding drought situation in Jharkhand.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से झारखंड में जो हमारे दस जिले सुखाड़ में हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आ गई है और कुछ जिले ऐसे हैं जो सूखे में हैं। वर्ष 1875 से लेकर 2012 तक का इतिहास यदि आप देखेंगे तो झारखंड के प्रायः सभी जिले ड्राउट में ही रहे हैं। उसका कारण यह है कि केवल दस परसेंट जो कृषि है, दस परसेंट जो खेती योग्य जमीन है उसमें हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं और नब्बे प्रतिशत जमीन आज भी सिंचाई के अभाव में है। यदि किसी कारण से मानसून नहीं होता है, पानी नहीं होता है तो हम कोई खेती नहीं कर पाते हैं। जिस लोक सभा चुनाव क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूँ - देवघर, दूमका, गोड्डा इनके अलावा सात और जिले हैं, यानि ये जिले सूखे से प्रभावित हैं। सूखा से प्रभावित होने के जो कारण हैं वे कारण मैंने आपको बताए हैं।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि एक्सलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में जो वाटर प्रोजेक्ट्स पिछले तीस-चालीस सालों से चल रहे हैं, चाहे वह बटेश्वर पंप नहर योजना, सुग्गाबथान योजना, बुढ़ई योजना या पुनासी योजना, इन सारी योजनाओं से यदि आप पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना चाहते हैं तो उसके साथ जोड़िए।

दूसरी बात यह है कि वहां के जो बैंक्स हैं वे न लोन देने के लिए तैयार हैं और न ही किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वे किसानों को न तो क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार हैं और न ही ऋण देने के लिए तैयार हैं।

आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए।

तीसरा, वहां ड्रिफ्टिंग वाटर की असुविधा है। जानवर के लिए वहां चारा नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि कुल एक हजार करोड़ रुपये का पैकेज झारखंड सरकार को देना चाहिए जिससे झारखंड के लोग सूखे से मुकाबला कर पाएं।